**रांची में उद्यान-कृषि संस्थान**

1625. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्यान-कृषि और विशेषकर परवल के लिए रांची में एक बड़ा संस्थान स्थापित किया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस संस्थान का एक छोटा यूनिट मुंगेर जिले के बरियारपुर क्षेत्र में स्थापित करने का विचार रखती है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** (क) भारतीय बागवानी अनुसन्धान संस्थान, बंगलोर के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने क्षेत्रीय केन्द्र के रूप में रांची में एक केन्द्रीय बागवानी परीक्षणात्मक केन्द्र स्थापित किया है । यह क्षेत्रीय केन्द्र परवल सहित क्षेत्र के लिए सभी फल तथा सब्जियों के सुधार के लिए अनुसन्धान कार्य चलाता है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन् ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

**कृषि कालेज तथा विश्वविद्यालय**

1626. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कुल कितने कृषि कालेज और कृषि विश्वविद्यालय हैं तथा उनमें कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार उनको प्रत्येक वर्ष में तीन महीने की अवधि के लिए किसानों के साथ खेतों पर काम कराकर व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्दूलाल चन्द्राकर)** : (क) देश में 22 कृषि विश्वविद्यालय, मुक्ताड़िया विश्वविद्यालय तथा 3 केन्द्रीय विश्वविद्यालय यानी बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, विश्व भारतीय तथा नार्थ ईस्टहिल यूनिवर्सिटी के अन्तर्गत 50 कृषि महाविद्यालय हैं । इन महाविद्यालयों में प्रत्येक वर्ष 5167 विद्यार्थियों के बी० एस० सी० (कृषि) डिग्री कार्यक्रम में प्रवेश पाने की क्षमता है । इन महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों की कुल संख्या लगभग 22300 है । इसके अतिरिक्त 31 गैर-सरकारी कृषि महाविद्यालय भी कार्य कर रहे हैं तथा आम विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं ।

(ख) इन महाविद्यालयों के शैक्षणिक कार्यक्रम संबद्ध विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक परिषदों द्वारा संचालित किये जाते हैं । तथापि, भारत सरकार इन संस्थानों का समन्वय तथा तकनीकी मार्गदर्शन करती है । जहां तक कृषि शिक्षा का सम्बन्ध है, भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने पहले ही बी० एस० सी० (कृषि) डिग्री के लिए माडल पाठ्यक्रम तैयार किया है जिसमें से 45 प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक क्षेत्र परीक्षण दिया जायेगा यह संख्या कृषकों के खेतों पर उत्पादनपरक क्षेत्रीय व्यावहारिक प्रशिक्षण, ग्रामीण कार्य अनुभव और उत्पादन प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिये जाने वाले कुल अपेक्षित 213 प्रशिक्षणार्थियों में से है ।

(ग) चूंकि प्रयोगात्मक प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त प्रावधान है इसलिए बी० एस० सी० (कृषि) डिग्री कार्यक्रम में आगे क्षेत्र प्रशिक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

**Safety Guidelines in Chemical Industries**

1627. SHRI K. VASUDEVA PANICKER: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) whether guidelines for maintenanace of safety in chemical industries have recently been issued by Government;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether guidelines for employees in various chemical units have also been laid down by Government; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR (SHRI P. ANJAIAH): (a) to (d). In the wake of Bhopal accident, various aspects and measures to be adopted to ensure safety and health of workers were considered in the meetings of Labour Secretaries and Labour Ministers of State Governments/Union Territory Administrations. On the basis of general consensus reached herein, a National Programme for Coordinated Action Plan for control of hazards and protection of occupational health and safety of workers in dangerous manufacturing processes has been drawn up. This action plan provides for specific and coordinated action to be taken by Central Government, State Governments, Employers and Worker Organisations. The National Action Plan has been forwarded to those agencies for initiating immediate action.

**Recommendations of the Second Press Commission**

1628. DR. BAPU KALDATE: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) what are the main recommendations made by Second Press Commission about Official Secrets Act which are still under consideration; and

(b) the time by when a final decision thereon is likely to be taken?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI V. N. GADGIL): (a) The Second Press Commission's main recommendations regardnig the Official Secrets Act are as follows:—

Section 5 of the Official Secrets Act 1923 may be repealed and substituted by other provisions suited to meet the paramount need of national security and other vital interests of the States as well as the right of the people to know the affairs of the State affecting them. It is essential in our view to restrict the operation of Section 5 by prescribing the types of information which need protection from disclosure. These types or categories will necessarily be broad, but primarily it will be the task of the executive to determine whether a document falls under any of the specified categories. In this respect we think that the provisions of part-II of the British Freedom of Information Bill may be adopted with appropriate modifications and changes. The other provisions in the Official Secrets Act may be carefully examined by an expert body to see which of them deserve modification and thereafter those provisions could also be incorporated in the new legislation proposed.

(b) It shall take quite some time before a final decision on these recommendations is taken.

**Imported edible oils supplied at subsidised rates**

1629. SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Will the Minister of FOOD AND CIVIL SUPPLIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that vanaspati manufacturers are using 60 per cent of imported oils supplied to them at subsidised rates;

(b) whether the imports of edible oils could be cut down substantially of using indigenous vegetable olis instead;

(c) whether with the use of indigenous oils, by vanaspati manufacturers the prices of vanaspati could be brought down benefiting millions; and

(d) if so, the steps proposed to be taken by Government for using more indigenous vegetable oils?